मंगलवार

34 साल से देहरादून का विश्वास

24 नवम्बर 2026

● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 303
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मानवता की प्रेरणा देती हैं

सीएम ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक प्रदेश की सुख–समृद्धि की कामना की

हमारे संवाददाता

उधमसिंहनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कार्तिक पूर्णिमा एवं सिख पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा एवं प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को सत्य, सेवा, समानता और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाएं समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के साथ ही जरूरतमंदों की निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। उनका संदेश आज भी संपूर्ण मानवता के लिए प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार सिख समाज की धार्मिक एवं



सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा ऐतिहासिक तीर्थस्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। उत्तराखण्ड में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना एवं रीठा साहिब के समीप धर्मशाला निर्माण जैसे कार्यों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के समन्वय की भूमि है। राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरिता राणा, दर्जाधारी राज्य मंत्री गंभीर सिंह धामी एवं किशन सिंह किन्ना, श्रीमती फरजाना बेगम, मेला समिति के अध्यक्ष शेर सिंह दानू सहित कई लोग मौजूद रहे।हिमांशु बिष्ट, श्री रनदीप पोखरिया, जिलाधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति, अपर जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती निर्मला बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

सड़कें नहीं, मौत के रास्ते’



◆हादसों के बाद जागता है सरकारी तंत्र, फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर
◆हर साल सैकड़ों जिंदगियां खत्म, आखिर किसकी है यह जवाबदेही
◆प्रदेश में सड़कों पर मौतों को रोकने के लिए हकीकत में किया क्या

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सड़कों पर अब सफर करना जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा होता जा रहा है। पहाड़ की सड़क हो या मैदान का हाईवे, हर तरफ मौत का खतरा मंडरा रहा है। कहीं बस खाई में गिरती है, कहीं कार नदी में समा जाती है और कहीं तेज रफ्तार वाहन परिवारों की खुशियां उजाड़ देते हैं। हर हादसे के बाद चीख-पुकार मचती है, सरकार संवेदना जताती है, मुआवजे का ऐलान होता है और जांच के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सड़कें वही, खामियां वही और हादसों का सिलसिला भी वही। आखिर उत्तराखंड की सड़कों पर लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों हो गई है?

यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2021 में 1405 हादसे हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 1846 हो गए। वर्ष 2025 में 1242 लोगों की मौत हुई और 2056 लोग घायल हुए। वर्ष 2026 के शुरुआती आठ महीनों में ही 1480 दुर्घटनाओं में 884 लोगों की जान जा चुकी थी। यह आंकड़े किसी एक जिले या किसी एक सड़क की कहानी नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रदेश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार और विभागों को पता है कि कौन सी सड़कें दुर्घटना संभावित हैं, कहां तीखे मोड़ हैं, कहां सड़कें संकरी हैं और कहां क्रैश बैरियर की जरूरत है, तो फिर समय रहते सुधार क्यों नहीं होता? प्रदेश में 2559 दुर्घटना संभावित स्थान चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 419 स्थानों पर सुधार कार्य अभी बाकी होने की जानकारी सामने आई है। क्या इन स्थानों पर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है?

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हादसे के बाद कार्रवाई का शोर तो खूब सुनाई देता है, लेकिन जवाबदेही शायद ही कभी दिखाई देती है। सड़क खराब थी तो जिम्मेदार कौन? सुरक्षा दीवार नहीं थी तो किसने अनदेखी की? क्रैश बैरियर नहीं लगे थे तो किस विभाग की जिम्मेदारी थी? वाहन में तकनीकी खामी थी तो फिटनेस प्रमाणपत्र किसने दिया? ओवरलोडिंग हो रही थी तो परिवहन और पुलिस की निगरानी कहां थी? इन सवालों के जवाब कभी सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा नहीं बन पाते। हर बार चालक की गलती, तेज रफ्तार या मानवीय चूक बताकर मामले को समेटने की कोशिश होती है। जबकि सड़क की बनावट, सुरक्षा इंतजाम, वाहन की स्थिति और सरकारी निगरानी भी दुर्घटनाओं की गंभीरता तय करते हैं।

उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के दावे लगातार किए जाते हैं। नए हाईवे बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और पर्यटन का विस्तार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़क निर्माण के साथ सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है? पहाड़ में सड़क चौड़ी करने के नाम पर कटान तो होता है, लेकिन कई जगह सुरक्षा दीवार, पैरापिट और क्रैश बैरियर जैसे इंतजाम पीछे छूट जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी स्थिति अलग नहीं है। तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, गलत दिशा में ड्राइविंग और यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी जारी है। शहरों में जाम और अव्यवस्थित यातायात है तो हाईवे पर रफ्तार का आतंक। यानी पहाड़ और मैदान, दोनों जगह खतरा है।

किसी हादसे में मौत होने के बाद सरकार मुआवजे की घोषणा कर देती है। लेकिन क्या किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की जिंदगी की कीमत कुछ लाख रुपये हो सकती है? क्या अनाथ हुए बच्चों का भविष्य मुआवजे से सुरक्षित हो सकता है? क्या उजड़ चुके परिवार को सरकारी संवेदना फिर से उसकी दुनिया लौटा सकती है? मुआवजा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है हादसों को रोकना। सरकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

चावल पर 20 प्रतिशत शुल्क!

चावल केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा, किसान की आजीविका और करोड़ों लोगों की थाली का आधार है। ऐसे में चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने की केंद्र सरकार की तैयारी ने एक बार फिर कृषि अर्थव्यवस्था और महंगाई नियंत्रण की सरकारी रणनीति को चर्चा में ला दिया है। विडंबना देखिए कि एक तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में शामिल है, दूसरी तरफ घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार निर्यात पर लगाम लगाने का विकल्प तलाश रही है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार कुछ चुनिंदा किस्मों के चावल के निर्यात पर करीब 20 प्रतिशत शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इनमें 100 प्रतिशत टूटे चावल और कुछ प्रीमियम गैर-बासमती किस्में शामिल हैं। हालांकि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है। सरकार विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श कर रही है। सरकार की दलील समझ से परे नहीं है। घरेलू बाजार में चावल की कुछ किस्मों की कीमतें बढ़ रही हैं। पोल्ट्री और पशु आहार उद्योग भी टूटे चावल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हैं। ऐसे में निर्यात पर शुल्क लगाकर घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निर्यात पर शुल्क लगाना ही महंगाई से लड़ने का सबसे प्रभावी रास्ता है? महंगाई का सबसे अधिक असर उस आम उपभोक्ता पर पड़ता है, जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करती है। अक्टूबर में चावल की महंगाई दर 12.51 प्रतिशत तक पहुंचने की खबर है। ऐसे में सरकार के सामने कीमतों पर नियंत्रण रखने का दबाव स्वाभाविक है। लेकिन महंगाई का समाधान केवल बाजार में आपूर्ति बढ़ाने तक सीमित नहीं हो सकता। उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बाजार में बिचौलियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि पर्याप्त सरकारी भंडार होने के बावजूद बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं तो पहले वितरण व्यवस्था की खामियों की पड़ताल होनी चाहिए। भारत का चावल निर्यात कारोबार लाखों किसानों, मिल मालिकों, कारोबारियों और परिवहन क्षेत्र की आजीविका से जुड़ा है। निर्यात पर शुल्क लगाने से भारतीय चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा हो सकता है। इससे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होगी और विदेशी खरीदार थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों की ओर रुख कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू किसानों से जुड़ा है। यदि निर्यात की मांग कमजोर होती है तो मिलों और व्यापारियों की खरीद प्रभावित हो सकती है। इसका असर अंतत: किसानों को मिलने वाले धान के मूल्य पर भी पड़ सकता है। किसान पहले ही मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती कृषि लागत, खाद और डीजल की कीमतों तथा बाजार के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि महंगाई नियंत्रित करने की कोशिश किसानों की आय घटाने का कारण न बन जाए। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरकारी भंडार है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक एक नवंबर तक भारत के पास चावल और बिना कुटे धान का कुल सरकारी भंडार 5.53 करोड़ मीट्रिक टन था, जो निर्धारित सरकारी लक्ष्य से लगभग चार गुना है। इसके बावजूद चावल की कुछ किस्मों की कीमतों में तेजी सरकार की बाजार प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जब देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है तो सरकार को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि बाजार में उसकी उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है। खुले बाजार में बिक्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। निर्यात शुल्क एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उसे एकमात्र समाधान मानना उचित नहीं होगा। भारत की जिम्मेदारी केवल अपने घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। दुनिया के अनेक देश भारतीय चावल पर निर्भर हैं। निर्यात नीति में बार-बार बदलाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। कृषि निर्यात में स्थिरता का अपना महत्व है। विदेशी खरीदार तभी दीर्घकालिक व्यापारिक समझौते करते हैं, जब उन्हें भरोसा हो कि नीतियां अचानक नहीं बदलेंगी। सरकार को यह भी समझना होगा कि हर किस्म के चावल की बाजार स्थिति एक जैसी नहीं होती। टूटे चावल का इस्तेमाल पशु आहार और औद्योगिक जरूरतों में होता है, जबकि प्रीमियम गैर-बासमती चावल का अलग उपभोक्ता वर्ग है। इसलिए सभी किस्मों को एक ही नजरिये से देखना व्यावहारिक नहीं होगा। खाद्य महंगाई पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी को सस्ता अनाज मिलना चाहिए और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना ही अच्छी आर्थिक नीति की असली परीक्षा है। सरकार को यह बताना होगा कि प्रस्तावित 20 प्रतिशत शुल्क किन किस्मों पर, कितनी अवधि के लिए और किस मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाएगा। निर्यात पर शुल्क लगाने से घरेलू आपूर्ति बढ़ सकती है, लेकिन इससे कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह सुनिश्चित नहीं है। वहीं निर्यातकों और किसानों पर इसके संभावित प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंतत: सवाल 20 प्रतिशत शुल्क का नहीं, सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं का है। क्या महंगाई का पूरा बोझ किसानों और निर्यातकों पर डालकर उपभोक्ता को राहत दी जा सकती है? खाद्य सुरक्षा के नाम पर निर्यात को नियंत्रित करना तभी उचित होगा, जब उसका लाभ वास्तव में आम उपभोक्ता तक पहुंचे और किसान की आय पर प्रतिकूल असर न पड़े। चावल की कीमतें थाली से जुड़ी हैं, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था खेत से शुरू होती है। सरकार को थाली और खेत, दोनों की चिंता करनी होगी।

बैणी-भुली योजना या 'चुनावी रिश्वत'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए बैणी-भुली योजना का दांव चल दिया है। सरकार इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन योजना की घोषणा का समय, लाभार्थियों की संख्या और किस्तों के भुगतान का चुनावी कार्यक्रम से मेल खाते संयोग ने इसकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में महिला सशक्तीकरण की पहल है या चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को आर्थिक प्रलोभन देकर साधने की कोशिश?

योजना को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार के ही ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर करार दिया है। यानी जिस योजना को सरकार महिला कल्याण की पहल बता रही है, उसके राजनीतिक लाभ की संभावना को लेकर खुद सरकार के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से संकेत दे दिया है। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलना स्वाभाविक है। बैणी-भुली योजना के तहत प्रदेश की करीब 5.23 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। ग्राम्य विकास मंत्री के अनुसार दिसंबर में पहली किस्त के रूप में प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। दूसरी किस्त मार्च में जारी किए जाने की बात कही गई है। इस योजना में स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को लाभ दिया जाना है। पहली किस्त के भुगतान का समय चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

योजना की घोषणा से ज्यादा चर्चा मंत्री भरत सिंह चौधरी के उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने इसे चुनाव में गेम चेंजर बताया। आखिर जब सरकार किसी योजना को चुनावी गेम चेंजर के रूप में देख रही है तो उसके पीछे राजनीतिक गणित को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? पांच लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सीधे धनराशि पहुंचाने की योजना का असर केवल लाभार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवारों और उनके सामाजिक दायरे तक इसका राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश भी होगी। भाजपा जानती है कि महिला मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। पिछले चुनावों में भी महिला मतदाताओं की भागीदारी और समर्थन ने राजनीतिक दलों के समीकरण प्रभावित किए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

◆पांच लाख महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रुपये डालकर धामी सरकार साधेगी चुनावी गणित
◆महिला सशक्तीकरण के नाम पर चुनावी साल में आर्थिक सहायता का दांव, मंत्री ने बताया गेम चेंजर
◆कांग्रेस ने पूछा- उत्तराखंड में 2027 के चुनाव से ठीक पहले ही क्यों आई महिलाओं की याद

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने योजना की समयसीमा और पात्रता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को महिलाओं की आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी है। प्रदेश में 35 से 40 लाख महिलाएं हैं, लेकिन योजना का लाभ सीमित संख्या में महिलाओं को ही मिलेगा। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि महिलाओं को चुनावी सहायता देने के बजाय स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे? दरअसल, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पहाड़ की महिलाएं खेती, पशुपालन, जंगल और घर की जिम्मेदारियों के बीच जीवन खपा रही हैं। पलायन के कारण गांवों में बढ़ता महिला श्रम, रोजगार के सीमित अवसर, बाजार तक पहुंच की समस्या और स्वरोजगार के लिए पूंजी का अभाव आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में महिलाओं को एकमुश्त आर्थिक सहायता देना निश्चित रूप से राहत पहुंचा सकता है, लेकिन क्या दस हजार रुपये की पहली किस्त इन बुनियादी समस्याओं का समाधान कर पाएगी?

महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल बैंक खाते में पैसा पहुंचाना नहीं है। इसका अर्थ महिलाओं को नियमित आय, रोजगार, बाजार, संसाधन और आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना भी है। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो उसे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

सत्ता बनाम सड़क, बीच में खड़ी पुलिस

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों एक नारा तेजी से चर्चा में है- जब-जब धामी डरता है, पुलिस को आगे करता है। यह नारा अब केवल किसी एक राजनीतिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह राजनीतिक प्रतिरोध का नया जुमला बनता जा रहा है। बैरिकेडिंग, पुलिस की तैनाती, हिरासत और प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव के बीच यह नारा धामी सरकार की राजनीतिक कार्यशैली पर विपक्ष के हमले का हथियार बन गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में सड़क और सत्ता के बीच संघर्ष तेज हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आंदोलन का रास्ता अपना रहा है तो सरकार सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस के माध्यम से प्रदर्शनों को नियंत्रित कर रही है। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विरोध की आवाजों को लोकतांत्रिक तरीके से सुनने के बजाय उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है?

पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में कई ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आए। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलनों में बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती चर्चा में रही। विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसी नारे को बुलंद किया। सितंबर में मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। कांग्रेस इसे सरकार की ओर से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताती रही, जबकि भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक विवाद को तूल देने की कवायद करार दिया। युवा कांग्रेस के रुद्रपुर प्रदर्शन में भी पुलिस बैरिकेडिंग और कथित लाठीचार्ज को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने धामी सरकार के खिलाफ यही नारा लगाया।

◆सड़कों पर गूंजता नारा, बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी होती सत्ता-पुलिस के सामने खड़ा विपक्ष
◆2027 के चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था बनाम लोकतांत्रिक विरोध की लड़ाई हुई तेज
◆कांग्रेस के आंदोलनों से लेकर यूकेडी के घेराव तक पुलिस बनी राजनीतिक टकराव का केंद्र

हालिया दिनों में मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान भी विरोध और असहमति के मामले सामने आए हैं। जौलजीबी मेले में धारचूला विधायक हरीश धामी और मुख्यमंत्री के बीच विवाद के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उठाने का अवसर नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने विधायक सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुख्यमंत्री ने इस व्यवहार को लोकतंत्र के लिए अनुचित बताया। वहीं श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेले के दौरान वरिष्ठ पत्रकार गंगा असनोड़ा थपलियाल को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रवेश से रोके जाने की घटना ने भी सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में प्रवेश रोकने के कारण और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होना जरूरी है।

पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रदर्शन के दौरान यातायात, सार्वजनिक संपत्ति और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व है। लेकिन इसी के साथ शांतिपूर्ण विरोध और असहमति व्यक्त करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। समस्या तब पैदा होती है, जब हर विरोध को कानून-व्यवस्था की चुनौती मानकर देखा जाने लगता है। क्या प्रशासन के पास प्रदर्शनकारियों से संवाद करने का कोई

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 12वें दिन भी जारी

हरिद्वार(आरएनएस)। विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को 12वें दिन भी आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने देवपुरा स्थित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में धरना-प्रदर्शन जारी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लंबित मांगों पर शीघ्र शासनादेश जारी करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। धरने पर बैठे संगठन की पदाधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं लंबे समय से विभागीय एवं गैर विभागीय कार्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन कर रही हैं, लेकिन उनके बढ़ते कार्यभार के अनुरूप मानदेय और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक लाभ और नियमित पेंशन की व्यवस्था भी नहीं है। संयुक्त मोर्चा ने मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और नियमित मासिक पेंशन देने की मांग उठाई। इसके अलावा कार्यभार के अनुरूप संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, उत्पीड़न एवं धमकी पर रोक लगाने तथा मांगों पर वार्ता के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा हम अपने हक की लड़ायी मजबूती के साथ लड़ेंगे। सरकार हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी तो आंदोलन को और तेज किया जायेगा। देवपुरा स्थित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में चल रहे धरने पर हेमा पंत, ममता, राधा, मंजु, रेनुका,बबीता,मधु वर्मा, उर्मिला, देवेश्वरी बहुगुणा, सोनिया खत्री, संगीता, सुनीता, रजनी, सुमन, बबीता, सुधा, देवेश्वरी लखेड़ा आदि मौजूद रहे।

यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज बढ़ाएगा बसों के फेरे

हरिद्वार(आरएनएस)। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने लगी है। दूसरे प्रदेशों और शहरों से बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने बसों की व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी की है। यात्रियों का दबाव बढ़ने पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो। स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोडवेज बसों से हरिद्वार पहुंचते हैं। इससे बस अड्डे पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। इसे देखते हुए निगम ने चालक और परिचालकों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बसों के संचालन और यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक विशाल चंद्रा ने बताया कि दोपहर बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने लगती है। यात्रियों के दबाव के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दूसरे प्रदेशों से आने वाले चालक-परिचालकों को भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। बस अड्डे की व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी।

राठ क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर स्थगित करने पर भड़के कांग्रेसी

पौड़ी(आरएनएस)। बीते रविवार को राठ क्षेत्र स्थित राइंका तिरपालीसैंण में प्रस्तावित स्वास्थ्य शिविर को राजनीतिक दबाव के कारण स्थगित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग में प्रदर्शन कर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के खिलाफ प्रदर्शन किया और खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन की मांग उठाई।सोमवार कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष विनोद नेगी और प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली की अगुवाई में शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे और परिसर में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने सीईओ दफ्तर का घेराव किया। विभाग में अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर कांग्रेस ने कड़ी निंदा की। कहा कि हफ्ते के पहले दिन ही विभाग में कोई जिम्मेदारी अधिकारी भी नहीं बैठा है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने बताया कि बीते रविवार को जिला पंचायत सदस्य नौड़ी सीमा पंत चमोली और रोटरी क्लब के सहयोग से राइंका तिरपालीसैंण में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रस्तावित था जिसमें श्रीनगर से 40 चिकित्सकों के साथ ही करीब आठ लाख रुपये की दवाएं निशुल्क बांटी जानी थी। शिविर के लिए प्रशासन और विभाग ने अनुमति भी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर सेठीक पहले राजनीतिक दबाव के कारण अनुमति निरस्त कर दी गई। उन्होंने शिविर स्थगित करने वाले का नाम सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई। इस मौके पर प्रमोद मंद्रवाल, मोहित सिंह, अनूप सिंह, गौरव सागर, आयुष आदि मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

'हमाम में सब नंगे है'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून/श्रीनगर। सत्ता जब सवालों से घबराने लगे और प्रशासन पत्रकारों की आवाज को रोकने का रास्ता तलाशने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र की बुनियाद में कहीं न कहीं दरार पड़ रही है। श्रीनगर गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैकुंठ चतुर्दशी मेले और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे। मंच पर सरकार की उपलब्धियों का बखान हो रहा था, विकास के दावे किए जा रहे थे और व्यवस्था अपनी पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत में जुटी थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे आयोजन की चमक के पीछे छिपे सत्ता के असहज चेहरे को सामने ला दिया। पत्रकार गंगा असनोड़ा थपलियाल को कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक पत्रकार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रवेश क्यों नहीं मिला? बड़ा सवाल यह है कि आखिर सत्ता और प्रशासन को गंगा असनोड़ा थपलियाल जैसी पत्रकार से किस बात का डर है? क्या उनकी मौजूदगी किसी व्यवस्था के लिए असुविधाजनक थी? क्या उनके सवालों से सत्ता का आत्मविश्वास डगमगाता है? या फिर पत्रकारिता को केवल सत्ता के गुणगान तक सीमित रखने की कोई नई परिपाटी विकसित की जा रही है?

गंगा असनोड़ा थपलियाल की पहचान एक निर्भीक पत्रकार के रूप में रही है। पत्रकारिता का मूल धर्म सत्ता के सामने सवाल खड़े करना, जनहित के मुद्दों को उठाना और व्यवस्था की जवाबदेही तय करना है। यदि किसी पत्रकार को महज इसलिए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रवेश से रोक दिया जाता है कि उसकी पत्रकारिता सत्ता के अनुकूल नहीं है, तो यह केवल एक व्यक्ति के साथ हुआ व्यवहार नहीं, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता की भूमिका पर चोट है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कोई निजी आयोजन नहीं था। बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी सार्वजनिक महत्व के आयोजन हैं। ऐसे कार्यक्रमों में जनता के साथ पत्रकारों की भी स्वाभाविक भागीदारी होती है। पत्रकार वहां सरकार की उपलब्धियां दिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन सवालों को सामने लाने के लिए भी पहुंचते हैं, जिनका जवाब जनता सरकार से चाहती है। आखिर लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका यही तो है। इस घटना ने एक बार फिर सत्ता और पत्रकारिता के रिश्तों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सरकारें अक्सर प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देती हैं, लेकिन जब कोई पत्रकार असहज सवाल पूछता है या सत्ता की कार्यशैली पर उंगली उठाता है तो उसके लिए दरवाजे बंद होने लगते हैं। यह दोहरा रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है।

◆उत्तराखंड राज्य में सत्ता को सवालों से इतना परहेज क्यों, यह यक्ष प्रश्न बना गया है आज ?
◆सीएम के कार्यक्रम में पत्रकार को प्रवेश से रोकना सत्ता के डर और मानसिकता पर सवाल
◆पत्रकार को रोकने घटना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सम्मान पर छेड़ी बहस

सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका को लेकर है। आखिर किसके निर्देश पर गंगा असनोड़ा थपलियाल को रोका गया? क्या प्रवेश रोकने का कोई अधिकृत आदेश था? यदि था तो उसके पीछे क्या कारण थे? और यदि यह फैसला मौके पर मौजूद अधिकारियों या सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों ने लिया तो क्या उनकी जवाबदेही तय होगी? मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई इस घटना पर मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सत्ता को यह समझना होगा कि पत्रकार उसके विरोधी नहीं होते। वे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उनकी आलोचना को व्यक्तिगत विरोध या राजनीतिक शत्रुता मानना सत्ता की संकीर्ण सोच को ही उजागर करता है। जो सरकार सवालों का सामना करने का साहस नहीं रखती, उसके विकास के दावों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आती है।

विडंबना देखिए कि जिस मंच से विकास, लोकतंत्र और जनभागीदारी के संदेश दिए जा रहे थे, उसी आयोजन में एक पत्रकार को प्रवेश से रोकने की घटना सामने आई। ऐसे में हमाम में सब नंगे हैं जैसी कहावत बरबस याद आती है। सवाल पूछने वाले को बाहर रखकर क्या सत्ता अपनी छवि चमकाना चाहती है? क्या अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में वही पत्रकार स्वीकार्य होंगे, जो सत्ता के अनुकूल सवाल पूछें? लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं है और पत्रकारिता सत्ता की कृपा पर चलने वाली व्यवस्था नहीं। गंगा असनोड़ा थपलियाल को कार्यक्रम में जाने से रोकने की घटना का सच सामने आना चाहिए। जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि आज एक पत्रकार के लिए दरवाजा बंद हुआ है, कल यह दरवाजा जनता की आवाज के लिए भी बंद हो सकता है।

चोरी की तारों के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। जस्सोवाला निवासी मौहम्मद अफजल ने सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि चोरों ने उसके मकान से बिजली की तारें चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने चैकिंग के दौरान दो लोगों को चोरी की तारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम साजिद पुत्र इरशाद व सददाम पुत्र वसिद निवासी जस्सोवाला बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

महिला ने वृद्धा को सम्मोहित कर लूटे गहने

संवाददाता

देहरादून। तिलक रोड निवासी प्रवीन कुमार ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी मां बाजार से घर की तरफ आ रही थी। जब वह घर के पास पहुंची तभी एक महिला ने उसकी मां को रोक लिया और उनको सम्मोहन व छलकपट कर उसकी मां के सोने के कंगन, कानों के झुमके व अगुंठियां उतरवाकर जेवरात अपने साथ ले गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच

संवाददाता

देहरादून। मानदेय बढाने व नौकरी की सुरक्षा सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया जिनको हाथीबडकला चौकी पर रोक दिया गया। जहां से जिला प्रशासन के माध्यम से उन्होंने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया



आज यहां आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। परेड ग्राउंड से राजपुर रोड, दिलाराम बाजार होते हुए वह हाथीबडकला चौकी के पास पहुंचे जहां पर पुलिस ने बैरकेडिंग डालकर उनको रोक दिया। इस दौरान कर्मचारियों व पुलिस में तीखी नोंक झोंक हुई जिसके बाद वह वहीं ध रने पर बैठ गये। जहां से उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उनका कहना था कि आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह ही मेहनत कर विभागों की व्यवस्था संभाल रहे हैं लेकिन उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। महंगाई के दौर में कम आय के कारण कर्मचारियों के परिवारों और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 से 20 वर्ष तक सेवाएं दे चुके कर्मचारियों को बिना कारण और नोटिस के नौकरी से हटाया जा रहा है। जिसको उन्होंने अमानवीय और तानाशाही रवैया बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उपनल की तर्ज पर अलग कारपोरेशन के समायोजन का रास्ता निकाल सकती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया है। वर्षो तक सरकारी विभागों में सेवाएं देने के बावजूद कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। न ही उचित मानदेय मिल रहा है और न ही नौकरी की सुरक्षा दी जा रह है।



श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम जींद रवाना

संवाददाता

देहरादून। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल की कबड्डी बालक वर्ग टीम अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए मंगलवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद, हरियाणा के लिए रवाना हुई।

आज यहां श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल की कबड्डी बालक वर्ग टीम अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए मंगलवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद, हरियाणा के लिए रवाना हुई। प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 नवंबर तक जींद में किया जाएगा, जिसमें टीम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। 13 सदस्यीय टीम में सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पीजी) कॉलेज, साहिया के सात खिलाड़ियों सहित विभिन्न महाविद्यालयों के खिलाड़ी शामिल हैं। टीम के कप्तानी रोहित नेगी और उपकप्तानी राहुल सिंह तोमर को सौंपी गई है। टीम में रोहित नेगी, राहुल सिंह तोमर, गोविन्द चौहान, नीरज तोमर, विकेश सिंह चौहान, प्रियांशु सिंह चौहान और वंश नेगी, सभी सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज, साहिया, कृष सजवाण एवं आयुष बगियाल, पंडित ललित मोहन शर्मा विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश, आयुष राज, तुला इंस्टीट्यूट, देहरादून, अंश लोहान, राजा महेंद्र प्रताप पीजी कॉलेज, गुरुकुल नारसन, अरुण भारती, श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय, चकराता और सचिन नेगी, वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर शामिल हैं। टीम के कोच अंकित शर्मा और टीम मैनेजर अनिल सिंह तोमर खिलाड़ियों के साथ रहकर टीम का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करेंगे। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की टीम प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पदक हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। क्रीड़ा परिषद के सचिव पुष्कर गौड़ ने टीम को रवाना करते हुए शुभकामनाएं दीं।

करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे 2 भूमाफिया गिरफ्तार

◆नकली व्यक्ति को खड़ा कर धोखाधड़ी से कराई थी फर्जी रजिस्ट्री

हमारे संवाददाता

देहरादून। भूमि बेचने के नाम पर नकली कागजात बनाकर असली भूमि स्वामी के स्थान पर फर्जी व्यक्ति को रजिस्ट्री के समय खड़ा कर करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे दो भूमाफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार बीती 14 सितम्बर को करन शर्मा निवासी सहस्त्र धारा रोड देहरादून द्वारा थाना राजपुर पर आकर तहरीर दी गई कि आरोपी संजय त्यागी आदि के द्वारा उनसे भूमि विक्रय करने के नाम पर धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए



व असली भूमि स्वामी के स्थान पर फर्जी व्यक्ति को रजिस्ट्री के समय खड़ा कर उनकी पत्नी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराकर भूमि विक्रय के नाम पर करोड़ों रुपए की धनराशि धोखाधड़ी से ली गई व अपना पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई व फरार हो गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी। मामले में नामजद आरोपी संजय त्यागी व उसके अन्य साथी घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे व मैन्युअल पुलिसिंग की मदद से जानकारी एकत्रित करते हुए बीती राम आरोपी संजय त्यागी व परविंदर कुमार को आईटी पार्क के पिछले गेट ,धोरण रोड से गिरफ्तार किया गया है। जिन्हे न्यायलय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व

संत राजिन्दर सिंह जी महाराज

भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक गुरु को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में पूर्ण गुरु को परमात्मा के समान माना गया है। आज दुनियाभर में हम सब गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उन जैसे पूर्ण गुरु सृष्टि की शुरूआत से ही इस धरती पर हमारी आत्मा को पिता-परमेश्वर से मिलाने के लिए आते रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म सन् 1469 ई0 को कार्तिक मास की पूर्णिमा को तलवंडी शहर (पाकिस्तान) में हुआ था।

गुरु नानक देव जी महाराज सिर्फ सिक्खों के लिए ही नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए थे जैसे संपूर्ण मनुष्य जाति उनके लिए थी। ऐसे महापुरुष इस धरती पर रोशनी की एक किरण बनकर आते हैं और अपने रूहानी नूर से 84 लाख जियाजून में फंसी हुई आत्माओं को पिता-परमेश्वर से एकमेक कर देते हैं। उनके मुख्य उपदेशों में "किरत करो, नाम जपो और वंड छको" प्रमुख हैं। जिससे तात्पर्य है कि इंसान अपनी मेहनत की कमाई करता हुआ प्रभु का सिमरन करे और सबके साथ मिल-बाँटकर खाए।

गुरुबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार के बारे में फरमाते हैं, "नानक दुखिया सब संसार" कि इस दुनिया में हरेक इंसान दु:खों से घिरा हुआ है। कोई न कोई दु:ख सबको लगा हुआ है। हर इंसान सोचता है कि सबसे ज़्यादा दु:ख मुझे है। अगर देखा जाए तो जब तकलीफ आती है तभी हम प्रभु को याद करते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर हम अपने कार्यों में मस्त हो जाते हैं। ये दु:ख और सुख का चक्र हमारे जीवन



में चलता रहता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम हमेशा-हमेशा के सुख को कैसे पा सकते हैं? इस बारे में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि "सो सुखिया जो नाम आधार।" यानि जो व्यक्ति पिता-परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ गया वही सुखी है। नाम के साथ जुड़ने के लिए हमें किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा, जो हमें अपनी दयामेहर से प्रभु की ज्योति और श्रुति से जोड़ देते हैं, जिसे गुरुबाणी में 'नाम' कहा गया है और जिसका अनुभव हम अपने अंतर ध्यान-अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं।

ध्यान-अभ्यास के द्वारा हमें अपने आपको असली रूप में देखते हैं। यह वो रूप है जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। वो आत्मा जो पिता-परमेश्वर का अंश है और उनके प्रेम से भरपूर है। वो आत्मा जो चेतन है, और जो हमें जान दे रही है। जब हमारी आत्मा पिता-परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करती है तो वो हर समय प्रभु-प्रेम की मस्ती की अवस्था में रहती है।

मस्ती की इस अवस्था को गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी में कहा है कि, "नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात"। जो नाम की खुमारी है, जो प्रभु का अमृत हमारे अंदर बरस रहा है, जब ध्यान-अभ्यास के द्वारा हम अपने अंतर में उसका अनुभव करते हैं तो उसकी मस्ती और उसका आनंद दिन-रात चौबीस घंटे हमारे साथ रहता है और जब हमारी आत्मा यह अनुभव करती है तो उसका मिलाप पिता-परमेश्वर से हो जाता है।

गुरु नानक देव जी महाराज ने "एक पिता एकस के हम बारिक" के संदेश को भी समस्त संसार में फैलाया। उनके इस उपदेश के अनुसार हम सब एक ही पिता-परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम आपस में प्रेम-प्यार से रहें और एक-दूसरे की मदद करें। जब हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम अपने भीतर प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं और ऐसे महापुरुष इसी प्रभु के प्रेम को हम सबको बांटने के लिए इस धरा पर आते हैं। जिससे कि हमें जिंदगी जीने की सही राह मिलती है। ऐसे पूर्ण गुरु हमें समझाते हैं कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य अपने आपको जानना और पिता-परमेश्वर को पाना को इसी जीवन में पूरा कर सकते हैं।

आईये! गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को हम सही मायनों में तभी मना सकते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें और उन पर अमल करें।

शब्द सामर्थ्य - 77

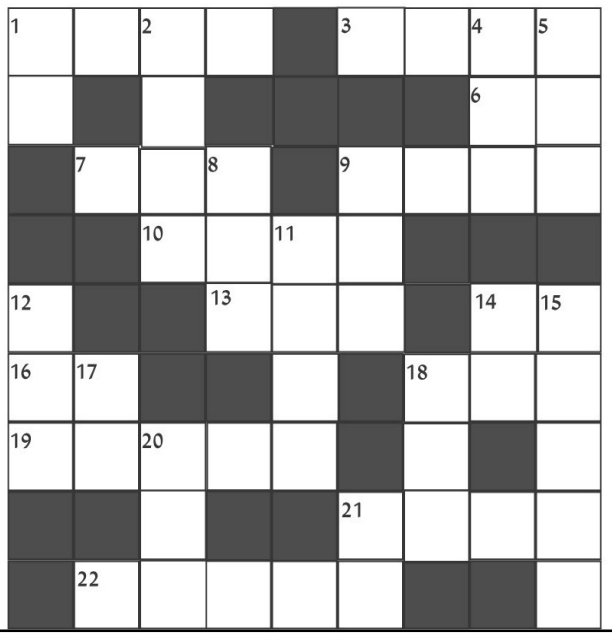
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. घुमाव-फिराव वाला, आड़ा-तिरछा, जो कठिन हो 3. कुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता 6. लोग, प्रजा 7. सीता, जनकनंदनी 9. सुंदर, कामना करने योग्य 10. क्रोधपूर्वक बोलने को उद्यत होना, जोश में आना, क्रोधातिरेक में चेहरे का लाल होना 13. अधीनता, मातहती, वश 14. दबाव, भार, वजन 16. हद, मर्यादा 18. प्रमाण-पत्र, प्रमाणिक कथन या बात 19. पछताना (मुहा.) 21. अनुचित मिश्रण, मिलावट 22. विफल, बेहोश, बौखलाया हुआ।

ऊपर से नीचे

1. सहारा, आश्रय, प्रतिज्ञा, संकल्प 2. परिश्रम 4. रात, रात्रि, निशा 5. पुत्र, बेटा 8. मूल्य, दाम 9. कपड़े का मोटा परदा 11. संदेश भेजना, उच्चारण कराना, कहलवाना 12. मृतकों को जीवित और रोगियों को स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, प्रेमपात्र की संज्ञा 14. देने की क्रिया, खैरात 5. कुमार्गी, दुराचारी 17. मस्तक, माथा, ललाट 18. प्रश्न, समस्या 20. सहायता, सहारा 21. पशुओं को खिलाने वाली हरी पत्तियां, तृण, तिनका।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 76 का हल

ज	द्दो	जे	ह	द	■	स	पू	त
ल	■	ब	ल	वा	न	■	■	द
म	ह	क	■	खा	म	खां	■	बी
ग्न	■	त	ल	ना	■	स	फ	र
■	म	रा	■	■	■	ना	टा	■
■	हि	■	स	■	■	■	फ	न
■	ला	ज	वा	ब	■	म	ट	र
मां	■	ग	■	सं	त	ति	■	भ
■	मा	त	ह	त	■	■	प	क्षी

महमूद के घर की एक बर्थडे पार्टी ने बदल दी जिंदगी, ऐसे बने नईम से जूनियर महमूद

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और अनोखे अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। इन्हीं में से एक नाम है जूनियर महमूद का। अपनी कॉमिक टाइमिंग, मजेदार डायलॉग डिलीवरी और शानदार डांस से लोगों को हंसाने वाले जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैय्यद था। उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्मी दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते अपनी अलग पहचान बना ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें जूनियर महमूद नाम कैसे मिला था? इसके पीछे एक ऐसी दिलचस्प कहानी है, जिसका कनेक्शन दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन महमूद के घर की एक बर्थडे पार्टी से है। जूनियर महमूद का जन्म 15 नवंबर 1956 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों और एक्टिंग में दिलचस्पी थी। उनके भाई फिल्मों के सेट पर फोटोग्राफर के तौर पर काम करते थे। ऐसे में नईम को भी कई बार शूटिंग देखने का मौका मिलता था। धीरे-धीरे फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। जूनियर महमूद के फिल्मों में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। एक बार उनके भाई उन्हें फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सेट पर ले गए थे। वहां उन्हें चुपचाप बैठने की हिदायत दी गई थी। उस समय फिल्म कितना नाजुक है दिल की शूटिंग चल रही थी। एक बाल कलाकार अपने डायलॉग बार-बार भूल रहा था। यह देखकर जूनियर महमूद से रहा नहीं गया और उन्होंने मजाक में टिप्पणी कर दी। जब निर्देशक ने उनसे पूछा कि क्या वह ये डायलॉग बोल सकते हैं, तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि वह जॉनी वॉकर के डायलॉग भी बोल सकते हैं। उनकी इसी बात ने उन्हें फिल्म में काम करने का मौका दिला दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल थी।

एक बार फिल्म सुहागरात की शूटिंग के दौरान दिग्गज अभिनेता महमूद की बेटी का जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने फिल्म की पूरी यूनिट को अपने घर बुलाया था। नईम भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें न्योता नहीं मिला। इस बात से वह काफी नाराज हो गए। उन्होंने महमूद से शिकायत करते हुए कहा कि क्या उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि उनके पिता कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं हैं? नईम की यह बात सुनकर महमूद ने उन्हें पार्टी में आने के लिए कहा। इसके बाद नईम ने वहां ऐसा डांस किया कि सभी देखते रह गए। उन्होंने फिल्म गुमनाम के मशहूर गाने हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं पर शानदार परफॉर्मेंस दी। उनका अंदाज महमूद को इतना पसंद आया कि उन्होंने नईम को अपना शिष्य बना लिया।

इस पार्टी में नईम की प्रतिभा देखकर महमूद काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने दादर के रंजीत स्टूडियो में नईम को बुलाया और उनकी कलाई पर गंडा बांधकर उन्हें अपना चेला बनाया। इसी के साथ उन्हें जूनियर महमूद नाम भी दिया। बस फिर क्या था, नईम सैय्यद की पहचान जूनियर महमूद के रूप में बनने लगी। जूनियर महमूद ने अपने लंबे फिल्मी करियर में सात अलग-अलग भाषाओं की करीब 265 फिल्मों में काम किया। गीत गाता चल, दीवानगी और अंखियों के झरोखे से जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। बाल कलाकार के तौर पर उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि निर्माता उनकी कॉमेडी और डांस को फिल्मों के लिए खास आकर्षण मानते थे। बाद में फिल्मों में पहले जैसी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने टेलीविजन की दुनिया का रुख किया। वह प्यार का दर्द है मीठा-मीठा प्यारा-प्यारा, एक रिश्ता साझेदारी का और तेनाली राम जैसे सीरियल्स में नजर आए। 8 दिसंबर 2023 को पेट के कैंसर के कारण 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भले ही आज जूनियर महमूद हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी, शानदार डांस और फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्से हमेशा दर्शकों की यादों में जिंदा रहेंगे।

जब प्रियंका चोपड़ा ने अभिषेक बच्चन के फोन से एक अभिनेत्री को मैसेज किया

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सिमी गरेवाल के साथ मुलाकात शो में अपने सह-कलाकार अभिषेक बच्चन के साथ की गई एक मजेदार शरारत को याद किया। प्रियंका ने बताया कि एक बार उन्होंने अभिषेक का फोन छुपा दिया था और उससे अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मैसेज किया था। गौरतलब है कि अभिषेक और रानी के अपने-अपने जीवनसाथी से शादी करने से पहले उनके बीच प्रेम संबंध होने की खबरें थीं। होस्ट सिमी गरेवाल ने प्रियंका से पूछा, क्या आपने कभी उनका मोबाइल चुराया था? प्रियंका ने बताया कि सबसे पहले अभिषेक ने ही उनका फोन चुराकर इस सब की शुरुआत की थी। प्रियंका ने आगे कहा कि उन्होंने इसे अभिषेक पर शरारत करने का मौका समझा। मैंने उसका फोन चुरा लिया और उसे छिपा दिया। मैंने उसके फोन से किसी को मैसेज भेजा... बस इतना कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम कहां थीं? क्या तुम... सिमी ने खुलासा किया कि प्रियंका ने अभिषेक के फोन से रानी को मैसेज किया था, जिसका जवाब रानी ने देते हुए लिखा, हाय एबी, क्या हुआ है तुम्हें? जब प्रियंका ने सिमी से पूछा कि उसे इस घटना के बारे में किसने बताया, तो सिमी ने जवाब दिया, खैर, मैं बहुतों को जानती हूं। हालांकि, प्रियंका को पहले से ही पता था और उसने कहा, मुझे यकीन है कि यह एबी ही है। इस बीच, प्रियंका और अभिषेक का पेशेवर रिश्ता काफी लंबा है। उनका पहला साथ में प्रोजेक्ट 2005 में था, जब उन्होंने रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लफमास्टर! में स्क्रीन शेयर की थी। इस ड्रामा में अभिषेक ने एक ठग का किरदार निभाया था, जबकि प्रियंका उनकी प्रेमिका सिम्मी के रूप में नजर आई थीं। 2008 में, प्रियंका और अभिषेक ने एक बार फिर द्रोणा के लिए साथ काम किया। गोल्डी बहल द्वारा निर्देशित इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म में अभिषेक मुख्य भूमिका में थे, जबकि प्रियंका उनकी रक्षक सोनिया के रूप में दिखाई दी थीं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना मेरे लिए बुरे सपने जैसा है: दीया मिर्जा



अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने के अनुभव को एक बुरे सपने जैसा बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है और कई यूजर्स इसे पीआर स्ट्रैटजी बता रहे हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना की। अभिनेत्री अपनी पोस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए लिखती हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना मेरे लिए बुरे सपने जैसा है, उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल का है और वे बेहद आपत्तिजनक इंसान हैं।

दीया मिर्जा ने अपनी इस पोस्ट के पीछे की कोई वजह या संदर्भ अभी तक साझा नहीं किया है। हालांकि, अभी तक न तो दीया मिर्जा ने इस पर कोई सफाई दी है और न ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से कोई जवाब आया है।

अभिनेत्री की पोस्ट में कोई स्पष्ट विवरण न होने के कारण सोशल मीडिया यूज़र्स इसे किसी आने वाले प्रोजेक्ट या विज्ञापन के प्रमोशन व पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग किसी संभावित विवाद को लेकर हैरान हैं। एक यूजर ने लिखा, ये भी पीआर ही होगा, आजकल सब वही है।

दूसरे यूजर ने लिखा, नवाजुद्दीन के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और दीया मिर्जा के फॉलोअर्स उसके आधे हैं।

एक अन्य यूजर ने लिखा, आजकल लोग काफी समझदार हो गए हैं और प्रमोशन वाली चीजों को आसानी से पहचान लेते हैं। पीआर टीमों को अब लोगों से सच में जुड़ने के लिए नए और अलग तरीके सोचने होंगे। नहीं तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब लोग कलाकारों के सच्चे पोस्ट और जरूरी बातों को भी नजरअंदाज करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये भी बस एक और प्रमोशन है।

एक और यूजर ने दीया मिर्जा की एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए लिखा, लेकिन उनकी एक्टिंग आपकी एक्टिंग से अच्छी है।

नेहा धूपिया को सता रहा रघु राम का डर!



टेलीविजन प्रोड्यूसर और अभिनेता रघु राम 12 साल बाद लोकप्रिय एडवेंचर रियलिटी शो रोडीज रीबर्थ में वापसी करने जा रहे हैं। शो की गैंग लीडर नेहा धूपिया रघुराम की इस वापसी से नाखुश नजर आ रही हैं। नेहा धूपिया ने कहा कि रघु की वापसी से वह बहुत घबराई हुई हैं। उन्होंने कहा, उनकी वापसी से मैं बहुत डरी हुई हूं। काश, वह इस सीजन में नहीं होते। गेम में वे पहले जो ट्विस्ट लेकर आए थे, उसने हमें काफी चौंकाया था। दरअसल, जब वे पहली बार आए थे, तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आगे कहा, अगली बार जब वे फिर से लौटे, तो वे हमें और भी ज्यादा चौंकाने वाले ट्विस्ट लेकर आए थे। अब तो बस यही चाहते हैं कि हम अपना काम आराम से कर लें और रघु अचानक से न आ जाएं।

बता दें कि रघु राम ने साल 2003 में शो रोडीज की शुरुआत और निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वो शो के पहले सीजन से लेकर 11वें सीजन तक बतौर जज और मास्टरमाइंड जुड़े रहे। उनके सख्त रवैये और तीखे सवालों के चलते उन्हें टीवी का सबसे कड़क जज माना जाता था।

साल 2014 में क्रिएटिव मतभेदों और प्रोड्यूसर्स के दखल के कारण रघु राम ने अपने भाई राजीव लक्ष्मण के साथ यह शो छोड़ दिया था। पूरे 12 साल के लंबे अंतराल के बाद, रघु राम एक बार फिर शो के 21वें सीजन रोडीज रीबर्थ में लौट रहे हैं। इस बार वे एक खास और नई शक्ति के साथ वापसी कर रहे हैं, जिससे वे कंटेस्टेंट्स के मौत या पुनर्जन्म जैसे बड़े फैसले करेंगे।

एमटीवी रोडीज सबसे लंबे समय तक चलने वाले एडवेंचर रियलिटी शोज में से एक है और इसका क्रेज भारतीय सीमाओं के बाहर भी कई देशों में देखने को मिलता है। रोडीज की लोकप्रियता को देखते हुए इसे दुनिया भर के 35 से अधिक देशों में प्रसारित किया जाता रहा है।

सरस मेले की तैयारियों का मुख्य विकास अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

हमारे संवाददाता

नैनीताल। एम.बी. इंटर कॉलेज मैदान, हल्द्वानी में 24 नवंबर से 3 दिसंबर तक राज्ट्रीय सरस मेले 2026-27 के सफल आयोजन हेतु मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुव्यस्थित बनाने हेतु जिला कमांडेंट होमगार्ड को 20 होमगार्ड जवानों की तैनाती के आदेष्ठा दिए इसके साथ ही उन्होंने स्टॉलों की व्यवस्था, पेयजल, ष्टौचालय, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तथा आगंतुकों के लिए बैठने एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देष्ठा दिए कि मेले की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं, ताकि देष्ठाभर से आने वाले स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों एवं उद्यमियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही मेले में आने वाले आमजन के लिए सुगम आवागमन, पार्किंग एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिष्ठिचत की जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राज्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादों को राज्ट्रीय मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए मेले को आकर्ज़क, व्यवस्थित एवं भव्य रूप से आयोजित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग मेले में प्रतिभाग कर स्थानीय उत्पादों से लाभान्वित हो सकें। निरीक्षण के दौरान 'परियोजना निदेष्ठाक ष्ठिाल्पी पंत सहायक परियोजना अधिकारी चंद्रा फत्याल जिला विकास अधिकारी संतोज़ पंत अधिष्ठासी अभियंता जल संस्थान रवि ष्ठांकर लोसाली जिला कृज़ि अधिकारी संतोज़ी जिला खाद्यय अधिकारी मनोज कुमार बर्मन' सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शराब के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने राणा मार्बल श्यामपुर के पास एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 41 पव्वे शराब के बरामद कर लिये। पूछताछ में उसने अपना नाम मुकुल देव सिंह नेगी पुत्र मान सिंह नेगी निवासी बुडकोट शेरा लम्बगांव बताया। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने भरत विहार से एक युवक को 30 पव्वे शराब के साथ गिरफ्तार किया जिसने अपना नाम कृष कश्यम पुत्र राजू कश्यप निवासी सर्वहारा नगर बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सू- दोकू क्र. 77

	1			4			7	
		6	9		2			1
	7			6		8		2
1							8	
	8			5		2		3
3		2			4		1	
	3		2			4		
		8		1	6			7
9			4				2	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र 76 का हल

3	9	6	8	2	5	4	7	1
8	2	5	1	7	4	6	3	9
7	1	4	6	9	3	8	2	5
1	8	9	3	6	7	2	5	4
2	6	7	5	4	8	1	9	3
5	4	3	9	1	2	7	8	6
6	7	2	4	3	9	5	1	8
9	5	1	7	8	6	3	4	2
4	3	8	2	5	1	9	6	7

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देहरादून साइक्लिंग क्लब ने पर्यावरण संरक्षण और मानवता का दिया संदेश

नगर संवाददाता



देहरादून। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर देहरादून साइक्लिंग क्लब द्वारा कोठाल गेट तक 45 किलोमीटर की विशेष साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं-मानवता, समानता, ईमानदारी, सेवा, प्रकृति प्रेम और आपसी भाईचारे-को जन-जन तक पहुँचाना रहा। साइकिल यात्रा प्रातः 5 बजे प्रेमनगर से प्रारंभ हुई। इससे पूर्व क्लब के साइकिलिस्टों ने प्रभात फेरी में सहभागिता की और गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हुए साइकिल यात्रा शुरू की।

यात्रा का मार्ग प्रेमनगर से पंडितवाड़ी, बल्लूपुर, किशन नगर चौक, यमुना कॉलोनी, बिंदाल पुल, घंटाघर, पैसिफिक मॉल, मसूरी डायवर्जन, साईं मंदिर, पुरानी मसूरी रोड होते हुए कोठाल गेट तक रहा। वापसी में साइकिलिस्ट कोठाल गेट से डीआईटी, रॉबर्स केव, सप्लाई चौक, गढ़ी कैंट, कौलागढ़ चौक और बल्लूपुर चौक होते हुए प्रेमनगर पहुँचे। यात्रा का नेतृत्व वरिष्ठ साइकिलिस्ट सुरेंद्र कुमार, जयन्ती प्रसाद गौड़ एवं राकेश थापा ने किया।

इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार ने साइकिलिस्टों को गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं-नाम जपो, किरत करो और वंड छको-के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर का स्मरण करना, ईमानदारी से मेहनत करना और अपनी कमाई एवं संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ साझा करना ही सच्चे जीवन का आधार है।

जयन्ती प्रसाद गौड़ ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की आधुनिक समय में प्रासंगिकता बताते हुए कहा कि आज के दौर में जब समाज भेदभाव, स्वार्थ, तनाव और पर्यावरण संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब गुरु नानक देव जी का समानता, सेवा, सद्भाव और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षाओं को केवल विचारों तक सीमित न रखकर अपने दैनिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।

राकेश थापा ने साइकिलिस्टों को अनुशासन बनाए रखने, नियमित रूप से साइकिल चलाने तथा स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया।

क्लब अध्यक्ष हरिसिमरन सिंह ने वरिष्ठ साइकिलिस्टों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने सभी साइकिलिस्टों को ईमानदारी, ईश्वर से जुड़ाव, जरूरतमंदों की सहायता और सही जीवन मूल्यों पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने सभी साइकिलिस्टों एवं सिख समुदाय को गुरु पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

उन्होंने पवणु गुरु पानी पिता माता धरति महतु श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने वायु को गुरु, जल को पिता और धरती को माता के समान सम्मान दिया है। यह संदेश आज देहरादून के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ बढ़ता वायु प्रदूषण, जल स्रोतों का प्रदूषण और हरित क्षेत्रों में कमी गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तव में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और हरित धरती के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। साइकिल का अधिकाधिक उपयोग प्रदूषण कम करने, यातायात की समस्या घटाने और स्वस्थ एवं हरित देहरादून के निर्माण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

इस यात्रा के दौरान देहरादून साइक्लिंग क्लब के साइकिलिस्ट को ओल्ड मसूरी रोड पर महिला शक्ति डॉ शिवानी पांडे, डॉ मुक्ता गोयल, डॉ प्रियंका पांडे, श्रीज मंजुषा, श्री मीनाक्षी और श्री शालिनी सक्सेना से मिलना हुआ जहां सेहत, वॉक , रनिंग और साइक्लिंग पर चर्चा भी हुई ।

इस साइकिल यात्रा में सुरेंद्र कुमार, जयन्ती प्रसाद गौड़, राकेश थापा, अजय अग्रवाल, हरिसिमरन सिंह, रिकी गोस्वामी, आरती, प्रणय पंत, आदर्श रावत, आर्यन चौहान, चित्रांग, मोहम्मद हारिस, अमन, प्रांजल कपूर, अनमोल चौधरी, प्रयाग नेगी, जय आदित्य टाटरान, सर्वज्ञ रावत एवं अर्नव रावत सहित अनेक साइकिलिस्टों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाएँ-ईमानदारी से जिएँ, जरूरतमंदों के साथ बाँटें, प्रकृति का सम्मान करें और मानवता की सेवा करें। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और हरित देहरादून के निर्माण में अपना योगदान दें।

भारतीय ज्ञान परंपरा आधरित परीक्षा में सरदार भगत सिंह महाविद्यालय के 67 विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग

नगर संवादाता



रुद्रपुर। सरदार भगतसिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित भारत बौद्धिक परीक्षा 2.0 का आयोजन किया गया। परीक्षा में महाविद्यालय के 67 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

यह परीक्षा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध प्राचीन ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं वैज्ञानिक चिंतन से परिचित कराना तथा भारतीय ज्ञान के प्रति उनकी समझ विकसित करना था।

परीक्षा में भारतीय कालदर्शन, तत्व एवं ब्रह्मांड, संख्यात्मक ज्ञान, भारतीय आरोग्य परंपरा, प्रकृति एवं चेतना, वैदिक गणित, भारतीय चिकित्सा पद्धति, शल्य चिकित्सा, अन्न उद्योग, राजधर्म, दर्शन, नगर नियोजन, भारतीय वास्तुकला, लोक प्रशासन परंपरा, भाषा विज्ञान, गुरुकुल एवं वैदिक परंपरा जैसे विविध विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए।

प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय, अभिकथन-कारण एवं वर्णनात्मक प्रश्न शामिल थे। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान-विज्ञान की व्यापकता, प्रासंगिकता एवं वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अवधेश नारायण सिंह ने विद्यार्थियों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। विद्यार्थियों को अपनी गौरवशाली परंपराओं, ज्ञान-विज्ञान एवं सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित होना चाहिए।

परीक्षा के सफल आयोजन में परीक्षा संयोजक एवं मूल्यांकन संयोजक डॉ बिपिन चन्द्र जोशी जी ने अहम भूमिका निभाई। इस परीक्षा को सफल बनाने में महाविद्यालय प्राध्यापक डॉ विकार खान, डॉ अनूप सिंह,डॉ भूपाल कार्की,डॉ दुर्गेश कुमार शुक्ला एवं डॉ मोनू बाला का विशेष सहयोग रहा।डॉ बिपिन चन्द्र जोशी जी ने कहा कि इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि, जागरूकता एवं गौरव की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। नोडल अधिकारी डॉ बसुन्धरा उपाध्याय ने सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएँ दीं।

मंदाकिनी नदी का स्नान घाट बदहाल, श्रद्धालु परेशान

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। नगर पंचायत क्षेत्र में मंदाकिनी नदी पर बना स्नान घाट बदहाली बना है। स्नान पर घाट पर कई जगह टूट-फूट और आसपास फैली गंदगी से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घाट से जुड़े कमरों में भी सफाई व्यवस्था नहीं है। धार्मिक महत्व रखने वाले इस घाट की दुर्दशा से श्रद्धालुओं में नाराजगी है।अगस्त्य मंदिर के मठाधीश योगेश बेंजवाल ने बताया कि प्रतिदिन भगवान अगस्त्य ऋषि के स्नान के लिए पहला जल मंदाकिनी नदी से इसी घाट के समीप से लाया जाता है। इस परंपरा के तहत पुजारी को नंगे पैर जल लेने पहुंचना पड़ता है लेकिन रास्ते की सफाई न होने और घाट की जर्जर स्थिति के कारण दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय निवासी पंकज सिंह ने बताया कि घाट की हालत लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है। जगह-जगह टूट-फूट के साथ कमरों में गंदगी फैली है। इससे यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं, नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी निकिता भट्ट ने बताया कि स्नान घाट का निर्माण नमामि गंगे परियोजना के तहत हुआ है और यह नगर पंचायत के अधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक मेले और त्योहारों के चलते पर्यावरण मित्र व्यस्त थे जिस कारण सफाई प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया शीघ्र व समय-समय पर यहां पर सफाई कराई जाती है।

सड़कें नहीं, मौत के रास्ते'...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

चाहिए कि उसने दुर्घटना के बाद कितनी सहायता दी, बल्कि इससे कि उसने दुर्घटना से पहले कितनी जिंदगियां बचाईं। उत्तराखंड में सड़क हादसे अब सामान्य समाचार बनते जा रहे हैं। हर कुछ दिनों में किसी परिवार के उजड़ने की खबर आती है और फिर अगली खबर आने तक व्यवस्था खामोश हो जाती है। यह खामोशी सबसे खतरनाक है। सरकार को बताना चाहिए कि चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर सुधार का काम कब पूरा होगा? खराब सड़कों और अधूरे सुरक्षा इंतजामों के लिए अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती? पहाड़ी मार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा और दुर्घटना के बाद त्वरित बचाव की व्यवस्था कितनी मजबूत है? अब केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने, जागरूकता अभियान चलाने और हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कठोर कार्रवाई, समयबद्ध सुधार और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की।

आखिर सड़कें जनता की सुविधा के लिए बनाई गई हैं या जनता की जान लेने के लिए? उत्तराखंड को विकास के चमकते आंकड़े नहीं, ऐसी सड़कें चाहिए जिन पर चलकर लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। हर हादसे के बाद शोक जताने वाली सरकार को अब यह जवाब देना ही होगा कि इन मौतों को रोकने के लिए उसने वास्तव में किया क्या है?

बैणी-भुली योजना या 'चुनावी रिश्वत'...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

के लिए बाजार, पहाड़ी कृषि के लिए बेहतर मूल्य और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने होंगे। भाजपा के सामने 2027 में सत्ता में वापसी और जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। ऐसे राजनीतिक माहौल में बैणी-भुली योजना भाजपा के लिए महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम बन सकती है।

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या महिलाएं आर्थिक सहायता को सरकार की उपलब्धि मानकर वोट देंगी या फिर रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की बदहाल बुनियादी सुविधाओं के आधार पर अपना फैसला करेंगी?सरकार के लिए यह योजना चुनावी लाभ का माध्यम हो सकती है, लेकिन जनता के लिए इसका मूल्यांकन केवल इस बात से होगा कि पैसा खाते में पहुंचा या नहीं, बल्कि इससे महिलाओं की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव आया।लोकतंत्र में कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सरकारी खजाने से होने वाले आर्थिक लाभ को राजनीतिक उपहार में बदलने की कोशिश पर सवाल उठना भी जरूरी है। बैणी-भुली योजना महिला सशक्तीकरण की पहल बनेगी या चुनावी रिश्वत का आरोप झेलेगी, इसका फैसला अंतत: उत्तराखंड की महिलाएं ही करेंगी।

सत्ता बनाम सड़क, बीच में खड़ी पुलिस...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

प्रभावी रास्ता नहीं है? क्या हर राजनीतिक असहमति का जवाब बैरिकेडिंग और हिरासत ही है? और क्या पुलिस की कार्रवाई में राजनीतिक निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है? यह सवाल केवल विपक्ष के नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़े हैं।

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी प्रकरण और सरकार की कार्यशैली को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। यूकेडी भी क्षेत्रीय अस्मिता, स्थायी राजधानी और मूलभूत सवालों को लेकर अपनी जमीन तलाश रही है। भाजपा विकास, कानून-व्यवस्था और केंद्र-राज्य की उपलब्धियों के आधार पर तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में यह नारा विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का राजनीतिक माध्यम बन सकता है। लेकिन इसके प्रभाव का आकलन केवल नारों या प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि उनके पीछे उठाए जा रहे मुद्दों और सरकार के जवाब से होगा।

दरअसल, लोकतंत्र में सरकार की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने बैरिकेड लगाए और कितने प्रदर्शनकारियों को रोका। उसकी असली कसौटी यह है कि वह अपने विरोधियों के सवाल कितने धैर्य से सुनती है। पुलिस को कानून का पहरेदार बने रहना चाहिए, सत्ता का राजनीतिक कवच नहीं। यही वह सवाल है, जिसका जवाब 2027 के चुनाव से पहले धामी सरकार को देना होगा।

मुख्यमंत्री ने झनकईया गंगा स्नान मेले का किया शुभारंभ

संवाददाता

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर खटीमा में आयोजित ऐतिहासिक झनकईया गंगा स्नान मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया।



आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर खटीमा में आयोजित ऐतिहासिक झनकईया गंगा स्नान मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शारदा तट पर पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत झनकईया एवं काला पुल के समीप नवनिर्मित पूर्णागिरि मंदिर क्षेत्र में स्नान घाटों के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा एवं श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झनकईया का ऐतिहासिक मेला धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और समृद्ध परंपराओं का संगम है। लंबे समय से आयोजित हो रहा यह मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। नई पीढ़ी भी पूरे उत्साह के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के समीप आयोजित होने वाला यह मेला दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों एवं आपसी सद्भाव को और सुदृढ़ करता है। भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी-बेटी का संबंध रहा है। दोनों देशों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में सीमांत क्षेत्रों के साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं व्यापारी पहुंचते हैं। थारू समाज सहित विभिन्न समुदायों की सहभागिता, पारंपरिक लोकगीत, लोकनृत्य और रीति-रिवाज इस मेले को विशेष पहचान प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन का अवसर भी प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से होती है। राज्य सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ पारंपरिक मेलों, महोत्सवों एवं सांस्कृतिक आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में खटीमा में आदि गौरव महोत्सव तथा देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय एवं सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं छात्रावासों जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा वन धन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि अतिक्रमणमुक्त कराई गई है। राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मेले के विस्तार एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग, नगर पालिका खटीमा एवं जिला पंचायत को आपसी समन्वय से स्नान घाटों, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरिता राणा, गंभीर सिंह धामी, किशन सिंह किन्ना, श्रीमती फरजाना बेगम, मेला समिति अध्यक्ष शेर सिंह दानू, हिमांशु बिष्ट, रनदीप पोखरिया, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार एवं श्रीमती निर्मला बिष्ट सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

मोटरसाईकिल चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने खुले स्थान पर खडी मोटरसाईकिल चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार परवल निवासी अब्दुल मन्नान ने प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह किसी काम से केहरी गांव गया था। उसने अपनी मोटरसाईकिल एक स्थान पर खडी की थी। लेकिन जब वह थोडी देर बाद वापस आया तो उसकी मोटरसाईकिल अपने स्थान से गायब थी।

कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में हुआ विस्तार

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों एवं अभियानों के सफल कार्यान्वयन हेतु उपाध्यक्ष व संशोधित जिलाध्यक्ष, विस्तारित/ महासचिवों को अतिरिक संचार एवं जिला प्रभारी नियुक्त किये करते हुए मुधसूधन सुंदरियाल को गढवाल मंडल प्रभारी बनाया गया।

आज यहां उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सोशल मीडिया विभाग) के नवनियुक्त पदाधिकारीगण व जिला प्रभारी कार्यभार की सूची जारी। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर ने सूची जारी करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देशानुसार आगामी संगठनात्मक गतिविधियों एवं अभियानों के सफल कार्यान्वयन हेतु पदाधिकारीगण व आंतरिक संचार एवं जिला प्रभारीगण नियुक्त किए जाता है। जिनमें से मधुसूदन सुंदियाल को गढवाल मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ओंकासर सिंह ढिल्लो को उपाध्यक्ष संगठन व राजकुमार को उपाध्यक्ष/ प्रभारी कुमाऊं मंडल नियुक्त किया गया। गोविंद प्रसाद को अल्मोडा का संशोधित जिलाध्यक्ष व कमल किशोर बिष्ट को कोटद्वार महानगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। सुश्री राजकुमारी पंवार को पौडी का महासचिव, अद्वैत बहुगुणा को पौडी महासचिव व विपिन नौटियाल को उत्तरकाशी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की गयी जिनमें से विनोद कुमार को उधमसिंह नगर, महेन्द्र टम्टा को काशीपुर नगर, हर्षवर्धन पंवार को हल्द्वानी महानगर, सूरज गुणवंत को नैनीताल, रवि पपने को अल्मोडा/रानीखेत, सतीश पंत को बागेश्वर, भुवन चौबे को पिथौरागढ, जगदीश कुमार को चम्पावत, जीतेन्द्र मेहता को डीडहाट, सतीश डिमरी को रूद्रप्रयाग, भास्कर बहुगुणा को चमाली, उदित विद्याकुल को रूडकी महानगर/ग्रामीण, पंकज सोनकर को हरिद्वार महानगर, दीपक गुप्ता को महानगर देहरादून/ पछवादून, दिनेश सकलानी को टिहरी गढवाल, ब्रजभूषण बहुगुणा को देवप्रयाग/ परवादून, विजय हिंदवाल को पौडी, आनंद बुटोला को पुरोला, विपिन नौटियाल को उत्तरकाशी, अद्वत बहुगुणा को कोटद्वार/ कोटद्वार महानगर, नीरज बहुगुणा को हरिद्वार ग्रामीण, घनश्याम फुलेरा को रूद्रपुर महानगर, भुवन अवस्थी को अतिरिक्त संचार व सुश्री राजकुमारी पंवार को अतिरिक्त संचार का कार्यभार सौंपा गया है। सभी पदाधिकारीगण/प्रभारीगण जनहित के मुद्दों के अधिकाधिक डिजिटल प्रसारण तथा जिला स्तर पर सोशल मीडिया संगठन को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उन्होंने अपेक्षा की है कि सभी पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चुनावी अभियान को घर-घर तक पहुँचायेंगे।

2027 जनवरी के आखिरी हफ्ते में लग सकती है आचार संहिता!

◆मार्च में मतदान की तैयारी



हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनावी हलचल तेज होने लगी है। संभावित चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक, प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव फरवरी के बजाय मार्च के पहले सप्ताह में कराए जा सकते हैं। इसके लिए जनवरी के आखिरी सप्ताह यानी 27 से 30 जनवरी के बीच आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, पांच से दस मार्च के बीच पहले चरण में मतदान कराए जाने का संभावित खाका तैयार होने की चर्चा है।

चुनाव की तारीखों में संभावित बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह बोर्ड परीक्षाओं को माना जा रहा है। दरअसल, फरवरी और मार्च के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने परीक्षा और मतदान की व्यवस्था के बीच तालमेल बैठाना बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में सरकारी स्कूलों के भवनों का इस्तेमाल मतदान केंद्रों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में शिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी चुनावी ड्यूटी में लगाए जाते हैं। दूसरी ओर, फरवरी से मार्च तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होना है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों और शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तैयार किए जाने की संभावना है। इसी वजह से जनवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लागू करने और मार्च के पहले सप्ताह में मतदान कराने का संभावित कैलेंडर तैयार किए जाने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से भी 27 से 30 जनवरी के बीच आचार संहिता लागू होने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। हालांकि, चुनाव की तारीखों और आचार संहिता को लेकर अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आठ जनवरी को आचार संहिता लागू हुई थी।

संभावित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की तैयारी बताई जा रही है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान हुआ था। इस बार मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड को भी शामिल किए जाने की संभावना है।

कार्तिक पूर्णिमाः हरकी पैड़ी समेत घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़



◆श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पर देशभर में श्रद्धालु पूजा-पाठ, दीपदान और दान-पुण्य करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान की भी विशेष मान्यता है। इसी परंपरा के तहत धर्मनगरी हरिद्वार में भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालु हरकी पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंचे।

गंगा में डुबकी लगाकर लोगों ने पूजा-अर्चना की और दीपदान किया। स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। सोमवार रात 12 बजे से स्नान पर्व समाप्त होने तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। यातायात का दबाव बढ़ने पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।

दिल्ली-मेरठ से आने वाले वाहन नारसन, मंगलौर, कोर कॉलेज, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी और शंकराचार्य चौक होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। बैरागी कैंप, बीएचईएल और ऋषिकुल मैदान में पार्किंग रहेगी। यातायात का दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक मार्ग में दिल्ली-मेरठ से आने वाले वाहनों को नगलाइमरती से लक्सर, फेरुपुर, जगजीतपुर, एसएम तिराहा, शनि चौक और श्रीयंत्र पुलिया होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा। दिल्ली-पंजाब-हरियाणा से देहरादून जाने वाले वाहनों को यातायात का दबाव बढ़ने पर सहारनपुर, मंडावर, भगवानपुर, सालियर, बिहारीगढ़ और मोहंड होते हुए देहरादून-ऋषिकेश भेजे जाएंगे। दिल्ली-मेरठ से देहरादून जाने वाली बसें रामपुर तिराहा, देवबंद, कोलकी टोल टैक्स, बिहारीगढ़ और मोहंड के रास्ते भेजी जाएंगी। मुरादाबाद-नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहन चिड़ियापुर, श्यामपुर और चंडी चौकी होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। नीलधारा और गौरीशंकर पार्किंग में वाहन खड़े होंगे। मुरादाबाद-नजीबाबाद से आने वाले बड़े वाहन डायवर्ट कर गौरीशंकर और नीलधारा पार्किंग में भेजे जाएंगे।

देहरादून-ऋषिकेश से आने वाले वाहन नेपाली फार्म, रायवाला होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। लालजीवाला पार्किंग में वाहन खड़े होंगे। देहरादून-ऋषिकेश से दिल्ली-मेरठ जाने वाले वाहन रायवाला, चंडी चौक और एनएच-344 होते हुए दिल्ली-मेरठ जाएंगे। देहरादून-ऋषिकेश से नजीबाबाद जाने वाले वाहन रायवाला, चंडी चौक और श्यामपुर होते हुए नजीबाबाद जाएंगे। देहरादून, ऋषिकेश और रायवाला की ओर से आने वाले ऑटो-विक्रम को यातायात का दबाव बढ़ने पर जयराम मोड़ तक ही आने दिया जाएगा। इसके आगे प्रवेश नहीं मिलेगा। ज्वालापुर और जटवाड़ा पुल की ओर से आने वाले ऑटो-विक्रम रानीपुर मोड़, देवपुरा होते हुए बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन की ओर जा सकेंगे। कनखल की ओर जाने वाले वाहनों को तुलसी चौक से यू-टर्न लेकर जाना होगा।

पार्किंग विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

देहरादून/हरिद्वार। देहरादून जिले के रायवाला स्थित हरिपुर कला में वाहन पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर रिवॉल्वर से चार राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और भाई-बहन बाल-बाल बच गए। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीती रात करीब 10 बजे हरिपुर कला के इंटर कॉलेज रोड की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवम लिंगवाल पुत्र नंदलाल ने रायवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि धर्मपाल उर्फ मुन्ना उनके घर के सामने पहुंचा और वहां खड़ी मोटरसाइकिल तथा पड़ोसी की कार को लात मारने लगा। इसके बाद आरोपी वाहन हटाने को लेकर गाली-गलौज करने लगा। शिकायत के अनुसार, जब शिवम और उनके परिजनों ने आरोपी के व्यवहार का विरोध किया तो वह भड़क गया। आरोप है कि और चार खोखे कारतूस बरामद किए हैं। उसने रिवॉल्वर निकालकर मौके पर मौजूद लोगों की ओर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी ने एक के बाद एक चार राउंड गोली चलाई। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। लोग घबराकर अपने घरों में चले गए। कुछ स्थानीय लोगों ने घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सूचना मिलने पर रायवाला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर रात तक कोतवाली में मौजूद रहा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आज सुबह आरोपी के खिलाफ जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गयी। जिस पर पुलिस टीम ने एक सूचना के आधार पर आरोपी धर्मपाल उर्फ मुन्ना (45) पुत्र प्रेम सिंह, निवासी इंटर कॉलेज रोड, हरिपुर कला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर

एक शिकायत, चार दरवाजे और 'इंतजार'

◆राजपुर थाने से डीजीपी कार्यालय और दो जिलों के एसएसपी तक भटके अंकिता के माता-पिता
◆हर जगह से मिला अगला ठिकाना व एफआईआर का आश्वासन, पुलिस के दरवाजों पर भटकते रहे
◆अंकिता हत्याकांड की एक शिकायत पर पुलिस महकमे में जिम्मेदारी तय करने वाला कोई भी नहीं

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में न्याय की मांग करना क्या इतना मुश्किल है कि पीड़ित परिवार को एक शिकायत पर कार्रवाई के लिए पूरे पुलिस महकमे के चक्कर काटने पड़ें? क्या थाने में दी गई शिकायत पर कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक जिले से दूसरे जिले में शिकायत भेज देने भर से पुलिस की जवाबदेही खत्म हो जाती है? अंकिता भंडारी के माता-पिता की आज की भागदौड़ ने पुलिस व्यवस्था के सामने ऐसे ही कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अंकिता के माता-पिता पहले राजपुर थाने पहुंचे थे और अपनी शिकायत दी थी। आज वे उसी शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति जानने दोबारा थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि शिकायत पौड़ी थाने भेज दी गई है। लेकिन क्या शिकायत पौड़ी भेज देना ही कार्रवाई है? क्या परिवार को यह बताने की जिम्मेदारी किसी की नहीं थी कि शिकायत पर अब तक क्या हुआ और आगे क्या कार्रवाई होगी?

राजपुर थाने से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो परिवार डीजीपी कार्यालय पहुंचा। उम्मीद थी कि प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च कार्यालय में उनकी पीड़ा सुनी जाएगी और मामले में जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन यहां डीजीपी के पीआरओ ने उन्हें देहरादून एसएसपी के पास भेज दिया। सवाल फिर वही है कि जब शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी तो तत्काल कार्रवाई की पहल क्यों नहीं हुई? देहरादून एसएसपी से मुलाकात के बाद परिवार को हरिद्वार एसएसपी के पास भेज दिया गया। इसके बाद अंकिता के माता-पिता हरिद्वार एसएसपी कैंप पहुंचे। यहां एसएसपी ने आश्वासन दिया कि मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए परिवार को कितने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? राजपुर थाने से पौड़ी थाना, डीजीपी कार्यालय से देहरादून एसएसपी और फिर हरिद्वार एसएसपी तक शिकायत की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या पुलिस के पास शिकायतों के निस्तारण की कोई जवाबदेह व्यवस्था नहीं है? क्या एक पीड़ित परिवार को यह बताने वाला भी कोई नहीं कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अंकिता के माता-पिता को ही अपनी शिकायत पर कार्रवाई के लिए इस तरह भटकना पड़ रहा है तो आम आदमी की शिकायतों का क्या हाल होगा? क्या पुलिस की संवेदनशीलता केवल भाषणों और प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह गई है? क्या न्याय मांगने वाले परिवार की पीड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण विभागीय औपचारिकताएं हो गई हैं?अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पहले ही उत्तराखंड की राजनीति, पुलिस और सत्ता प्रतिष्ठान को कठघरे में खड़ा किया है। अब उसके माता-पिता की यह भागदौड़ व्यवस्था की संवेदनशीलता पर एक और सवालिया निशान है। परिवार को फिलहाल एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन कार्रवाई का विकल्प नहीं हो सकता।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।